07/01/2026

आकाशवाणी ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुङ ने लोक भवन, ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. परनाइक से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए राज्य के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन तथा राज्य की पूरी पुलिस बल की सराहना की। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गृह मंत्री के दृढ़ नेतृत्व की भी प्रशंसा की। राज्यपाल ने गत 8 दिसंबर 2025 को आंजाव जिले के चागलागाम में हुए हादसे के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी करते हुए जन सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और एहतियात के तौर पर रात्रि के समय वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जिला पुलिस को देने की सलाह दी। इसके अलावा, राज्य में अवैध घुसपैठियों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल कार्रवाई करने की भी सिफारिश की।

0000000000000000000000

मुख्यमंत्री पेमा खांदू ने बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार कागजी प्रणाली की जगह डिजिटल इनर लाइन परमिट -ILP व्यवस्था लागू करने वाली है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की एक टीम ने इस पर शोध पूरा कर लिया है और जल्द ही प्रस्ताव को विधानसभा के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। डिजिटल ILP प्रणाली से राज्य में प्रवेश करने वालों की निगरानी और नियंत्रण को और सशक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम के तहत श्रमिकों को लाने वाले नियोक्ताओं की जवाबदेही तय होगी और सभी श्रमिकों का विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद नियोक्ताओं को श्रमिकों को वापस भेजने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि BEFR अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो एदवोकेट जनरल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। साथ ही, मुख्य सचिव के माध्यम से उपायुक्तों को अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

0000000000000000000000

उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने अंजाव जिले की 1200 मेगावाट की क्षमता वाली कालाई-II जलविद्युत परियोजना की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह परियोजना राज्य की प्रमुख और व्यवहार्य जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। बैठक में पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन - R&R तथा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री ने संबंधित एजेंसियों को सभी स्वीकृतियों में तेजी लाने और एक सौ बत्तीस केवी तेजू-हालाइपानी ट्रांसमिशन लाइन सहित विद्युत व्यवस्था के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार के देरी से बचा जा सके।

0000000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पासंग दोर्जी सोना ने राज्य पर्यटन विभाग के नए ब्रांड अभियान **"टेक ए न्यू टर्न इन अरुणाचल**" का शुभारंभ किया। यह अभियान यात्रियों को केवल दृश्यों से परे स्थलों तक सीमित न रहकर राज्य की कहानियों, लोगों और ऐसे अनुभव जो राज्य को परिभाषित करते हैं। **"बियॉन्ड मिथ्स एंड माउंटेन्स"** पर आधारित यह अभियान तवांग, जीरो, आनिनी, नामसाई, दोंग और मेचुका जैसे पर्यटन स्थलों को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है, जहां आध्यात्मिक विरासत, स्वदेशी संस्कृति, साहसिक पर्यटन और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और अनुभव आधारित पर्यटन पर कैंद्रित अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे आकर्षक और अर्थपूर्ण पर्यटन स्थलों में तेजी से उभर रहा है।

0000000000000000000000

अरुणाचल प्रेस क्लब - APC द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांदू को ऋ तीन सूत्रीय मांग सौंपा गया। APC अध्यक्ष अमर सांगनो ने कहा कि प्रमुख मांगों में लंबे समय से लंबित कार्यरत पत्रकार पेंशन योजना को

लागू करना शामिल है। अन्य मांगों में जिला उपायुक्तों एवं जिला प्रशासन को जिला प्रेस क्लबों के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाएं साझा करने तथा आधिकारिक संचार उन्हीं के माध्यम से करने के निर्देश देना, एवं जिला प्रेस क्लबों को कार्यालय स्थान, भूमि या बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि इन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने APC, APUWJ और जिला प्रेस क्लबों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है।

000000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर स्थायी पीठ के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में 25 रिक्त पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026 होगी।

000000000000000000000

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार यदि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो वे सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

00000000000000000000000

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME उद्यम मंत्रालय तथा निउम्ही फाउंडेशन के सहयोग से नामसाई जिले के टाउन क्लब हॉल में आयोजित किया गया।

00000000000000000000000